



# सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

( ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध )

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर ( छ.ग. )



अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 1/2022

दिनांक : 01/01/2022

## मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

### विषय : नए वर्ष का उगता सूरज, सबके लिए सुनहरा पल हो

नव वर्ष 2022 के अवसर पर हम मध्य क्षेत्र के समस्त बीमा कर्मियों के साथ ही देशभर के बीमा कर्मियों और मेहनतकश जनता के प्रत्येक हिस्से के साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करते हैं। हम साथ ही यह अपेक्षा करते हैं कि नव वर्ष हमारे साथियों के लिए नई उम्मीदों और आशाओं के साथ एक बेहतर समाज और हालात के लिए संघर्षरत दुनिया के अवाम के लिए नई किरणों की रोशनी का आगाज लेकर आए।

निश्चय ही कोरोना महामारी की काली स्याह ने विगत वर्ष की भयावह त्रासदी मचाई। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई उसमें भारी संख्या में हमारे अपनों को हमने खोया। हमने पहले भी कहा था और शायद आज पुनः यह दोहराने की आवश्यकता है कि मुनाफे की अंधी दौड़ में जुटी पूंजीवादी दुनिया ने जिस तथाकथित उदारवादी आर्थिक नीतियों को थोपा है उसकी अमानवीयता की सजा भी विश्व और देश के हर हिस्से में नागरिकों ने भोगा है। 2021 की दर्ज होती इतिहास में उसकी काली स्याह हमेशा ही मानव समाज के भावी इतिहास में भी गूंजेगी। ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते लोग भी, गंगा की छाती पर तैरती लाशें, निजी अस्पतालों में जगह की मारामारी और लोगों की मजबूरी का लाभ उठाने मचाई गई लूट के खेल से शायद सबकी रुहें ही कांप जाएं। इस काले इतिहास के पन्नों ने यही सबक दिया कि सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ने के जरिये 'व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं', 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के नारों का असली मकसद ही निर्मम लूट और शोषण को जायज ठहराना है। इसलिए हमने देखा सर्वाधिक विकसित पूंजीवादी देशों और घुर दक्षिणपंथी रुझान वाले देशों की जनता इसकी सर्वाधिक शिकार हुई। इसकी तुलना में नवउदारवादी नीतियों के विपरीत, जनपक्षधर हस्तक्षेपकारी समाजवादी विश्व ने इसका कहीं कारगर ढंग से न केवल स्वयं मुकाबला किया वरन् विश्व के दूसरे लोगों की

मदद भी की। क्यूबा इसका नायाब उदाहरण है। इस रोशनी में विश्व की मेहनतकश जनता अपने जीवन के असल /-खलनायकों की पड़ताल कर एक बेहतर विश्व के निर्माण के अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का नववर्ष में एक संकल्प उद्घोषित करेगी यह हमारा विश्वास है। नववर्ष के आगमन के ठीक पूर्व चिली में वामपंथी समर्थक गैबारियेल बोरिक की राष्ट्रपति के रूप में जबर्दस्त विजय इसी संदेश की अभिव्यक्ति है।

जिन हालातों का जिक्र हमने ऊपर किया है उनमें से हरेक पहलू को भारत की आम जनता ने भी भोगा है। बीमा कर्मियों के एक बड़े हिस्से ने भी अपने सबसे नजदीकी और परिजनों को इस साल खोया है। हमारे बीच के कई प्रिय, प्रतिबद्ध और संगठन तथा संस्था के बेहतरीन साथियों को भी इस महामारी ने लील लिया है। लेकिन इस भयानक दौर में पीड़ित जनता को राहत देने उठाने की बजाय 'आपदा को अवसर में बदलने', 'लोकल फॉर वोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा उछालकर रेल से लेकर हवाई सेवा, एयर इंडिया से लेकर कोयला, ऊर्जा, इह्यापात, रक्षा और बैंक से लेकर बीमा देश की सार्वजनिक संस्थाओं की निजी पूंजी की निर्मम लूट के लिए अंधाधुंध निजीकरण यानि न्यू इंडिया के नाम पर सेल इंडिया की वर्तमान सरकार की देश विरोधी मुहिम का साक्षी रहा यह वर्ष। यह वर्ष साथ ही वर्तमान सरकार की अलोकतांत्रिक और जनविरोधी चरित्र का भी साक्षी रहा। संसद के अंदर और सड़कों पर जनता के भारी विरोध के बावजूद श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिता में तब्दील कर देने, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाईपलाईन के नाम पर सार्वजनिक संस्थाओं को मंडियों में बदलकर नीलाम करने और पेट्रो पदार्थों की मनमानी कीमतों से जनता की जेबों पर डाका डालकर करोड़ों रुपये वसूल किये जाने की उनकी अमानवीयता को भी हमने देखा। कोरोना के चलते बदहाल अर्थव्यवस्था, करोड़ों लोगों की घटती आमदनी, चरम

बेरोजगारी और असंख्य लोगों को रोजगार से हाथ धोने, कारखानाबंदी के दौर में इसी अवधि में चंद पूंजीपतियों के हाथों बढ़ते पूंजी के केंद्रीकरण और उनके मुनाफे में 250 से 430 प्रतिशत की भारी भरकम बढ़ोत्तरी का भी यह साल साक्षी रहा। ऐसे समय में जनता को मदद पहुंचाने कदम उठाने के मामले में सरकारी उदासीनता, टीकाकरण अभियान में भी उनके उपेक्षापूर्ण रुख के चलते सर्वोच्च न्यायालय की सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणियों का भी साक्षी रहा यह वर्ष।

सरकार से इस जनविरोधी रुख के विरुद्ध कृषि कानूनों में परिवर्तन वापस लेने की मांग को लेकर एक साल से भी अधिक समय तक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 500 से भी अधिक विकास संगठनों की अभूतपूर्व एकताबद्ध संघर्ष का अभूतपूर्व मिसाल का भी साक्षी रहा वर्ष 2021। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या-क्या आरोप जड़ डाले, हर किस्म की प्राकृतिक विपदा हो या सरकारी दमनतंत्र, या फिर केंद्र सरकार के मंत्रीपुत्र द्वारा अपनी जीप से आंदोलनकारियों को कुचल देने के चरम अमानवीय कृत्य से किसान आंदोलन को खत्म करने चलाए गए कुचक्र या फिर सांप्रदायिक नारों और धार्मिक आस्थाओं के विभाजनकारी हथकंडों का उपयोग कर उन्हें बांटने के लिए चलाए गए प्रचार माध्यमों और गोदी मीडिया के गठजोड़ के घृणित अभियानों, किसानों ने एकजुटता के साथ इन सबका धीरज और अहिंसक आंदोलन के जरिए पूरी एकता से मुकाबला किया और अंततः सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने मजबूर किया। 2021 इस मामले में एक नये इतिहास का साक्षी बना। सरकार की देशविरोधी, किसान, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कोयला मजदूर, बैंक, बीमा कर्मियों, रक्षा कर्मियों, इस्पात कर्मियों, संगठित-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी हड़ताली कार्यवाहियों और किसानों-मजदूरों के साझे संघर्षों की मजबूत दीवार की नई इबारतों का भी यह वर्ष साक्षी रहा है। निश्चय ही नये वर्ष में यह एकता और मजबूत होगी तथा 23-24 फरवरी 2021 को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर कृषि कानूनों की तरह श्रमिक विरोधी और सार्वजनिक संस्थाओं की बिक्री की देशविरोधी नीतियों के भी पीछे धकेलने अपनी लड़ाई को और तीखी करेगी। नववर्ष में हमारा यही विश्वास है।

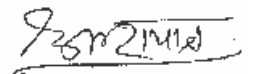
राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम व आम बीमा क्षेत्र की सार्वजनिक संस्थाओं को कमजोर करने के सरकारी षड़यंत्रों का भी साल 2021 साथी रहा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को तमाम विरोध के बावजूद भाजपानीत वर्तमान केंद्र सरकार ने 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया है और उसने एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर इसके आईपीओ जारी करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है।

सरकार ने घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में कभी भी वह यह कदम उठा सकती है। आम बीमा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के लिए उसने संसद में विषय के विरोध को दबाने मार्शल तक का उपयोग कर जिबना कानून में संशोधन पारित कर लिया। बैंक के निजीकरण के लिए वह बैंकिंग कानून में भी संशोधन करने जा रही है। पूरे देश में सरकार के इन कदमों के विरुद्ध एआईआईईए के नेतृत्व में महर सांसदों से भेंट, बीमाधारकों व आमजनों के मध्य, कन्वेंशन, गोष्ठी, चर्चा, परिचर्चा इत्यादि का जन अभियान जोरों पर है। निश्चय ही सरकार के राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग को बर्बाद करने के हर कदम दर कदम, इंच दर इंच इसका करारा जवाब देने हमें नववर्ष में अपने अभियानों को और तीव्र करना होगा।

एलआईसी में लंबे संघर्ष के बाद सभी श्रेणियों के संयुक्त मंच की एकता के जरिए एआईआईईए के नेतृत्व में एक बेहतरीन वेतन पुनर्निर्धारण पुनः प्राप्त करने की सफलता गाथा का भी वर्ष 2021 साक्षी रहा। हमने अनेक लंबित मुद्दों के समाधान और अन्य सुविधाओं में सुधार भी हासिल किये। नये सहायकों के लंबित पैनल से कुछ बेरोजगार युवाओं को और साथ ही नये ऊर्जावान, प्रतिभाशाली युवाओं को इस उद्योग और संगठन के परिवार का हिस्सा बनाये। निश्चय ही वर्ष 2021 इस संदर्भ में एक उपलब्धियों का वर्ष रहा है। इनमें से हरेक उपलब्धि की हिफाजत करते हुए तमाम आक्रमणों का मुकाबला करने एकताबद्ध होकर संगठन को संगठित करने फिर एक बार प्रतिबद्ध होने की उद्घोषणा करेंगे। यही हमारा विश्वास है। नववर्ष, नवतेवर, नव कलेवर के साथ हम हमारे और देश के प्रत्येक हिस्से के नागरिकों और आमजनों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा निजी एवं सार्वजनिक जीवन में हमारे समक्ष उपस्थित सभी दायित्वों का पूरी एकता और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करते हुए एक बेहतर कल को हासिल करेंगे। हम हमारे संस्थान व संगठन की हर परिस्थिति में रक्षा कर और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ नववर्ष 2022 का स्वागत करते हुए आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करते हैं।

**एक बेहतर कल की शुभकामना के साथ...**

**आपका साथी**



**( डी.आर. महापात्र )**

महासचिव



